(ङ) सिक्किम के राज्यपाल ने सिक्किम को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में मुझे पत्र लिखा था। उन्हें सूचित कर दिया गया था कि तीसरी वायु सेवाओं पर निर्णय लेते समय सघटोक को ध्यान में रखा जाएगा।

Outstanding Disputes between Bank of India and Andhra Steel Corporation Limited

4425. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether further representations have been made to Government of India and to the management of Bank of India, Bombay by the Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Limited, Bangalore in the matter of settling all outstanding disputes and differences between the Bank of India and Andhra Steel Corporation Limited;

(b) if so, the details of such representations;

(c) whether the Bank of India has been insisting for certain unworkable propositions to be fulfilled by the management of Andhra Steel Corporation Limited; and

(d) if not, the reasons for non-settlement of disputes when the Company is being managed very profitably?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Looking to its past experience with the unit and considering its large stake in the company, the Bank of India has stipulated terms and conditions on use of funds and payment which are essential. The dispute remains unresolved merely because these terms and conditions are not being fulfilled by the company.

Introduction of Lead Bank Scheme in Tripura

4428. SHRI SACHINDRA LAL SINGHA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Lead Bank Scheme has been introduced in Tripura;

(b) if so, the details of the functioning of the Lead Bank of the State;

(c) whether the Lead Bank of the State formulated any State Credit Plans on any district credit plans;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the action taken up-to date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) to (d). The Lead Bank Scheme has been in operation in Tripura since its inception in 1969, the 'Lead' responsibility being with the United Bank of India. As the lead bank, United Bank of India had undertaken a survey of Tripura State (then a Union Territory), identified potential growth centres for branch expansion, enlarged its branch network from one in June 1969 to 23 in June 1978 and increased the flow of its credit to small borrowers for productive ventures in the priority sectors from a negligible level in June 1969 to Rs. 275 lakhs in June 1978. The lead bank has also formulated district credit plans to secure coordinated joint action on the part of all the financial institutions operating in the State to progressively meet the identified credit requirements of different sectors on a district by district basis. The details of the credit plans are given in the *Annexe*.

(e) The targets envisaged in the credit plans have been allocated among all the participating financial institutions for implementation.

Particulars of the District Credit Plans prepared by United Bank of India for Tripura

(Rs. in lakhs)

District	Period of plan	Credit Outlays			
		Agriculture	Industry	Services	Total
1	2	3	4	5	6
North-Tripura	1978-80	275·50	62·95	66·66	405·00
South-Tripura	1978-80	321 95	110·35	76·56	508·80
West-Tripura	1978-80	442 30	101·15	232·10	775·55

लद्दाख में नुबारा में तत्तापानी का विकास

4429. श्रीमती पार्वती देवी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख मे नुबारा में तत्तापानी नामक स्थान बहुत विख्यात है और पर्यटको के लिये आकर्षण का केन्द्र है, क्या सरकार इस स्थान को सुन्दर बनाने और इसका विकास करने पर विचार करेगी ,

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्यटको को नुबारा जाने की अनुमति नही दी जाती है,

(ग) क्या सरकार इस बारे मे उपयुक्त निर्णय लेकर इस क्षेत्र का विकास करने पर विचार करेगी, और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) नुबारा घाटी ऐसे प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित है, जहां पर्यटको के प्रवेश की अनुमति नही दी जाती। इसलिए इस घाटी में स्थलो का विकास करने से पूर्व पर्यटक यातायात पर लगे प्रतिबन्धो को उठा लेना आवश्यक है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग का यह भी सुविचारित दृष्टिकोण है कि तत्काल आवश्यकता इस क्षेत्र के पर्यावरण तथा सस्कृति सबधी विशिष्टताओ को सुरक्षित रखने की है, जो इस क्षेत्र के मुख्य पर्यटक आकर्षण हैं। अत राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि लद्दाख मे पर्यटन विकास के लिए एक महा योजना इस बात को सुनिश्चित करत हुए तैयार की जाए कि इस क्षेत्र के पर्यावरण तथा संस्कृति सबधी भाव को विनष्ट किए बिना अपेक्षित पर्यटक सुविधाओ की व्यवस्था की जाए।

कर अपवंचन के मामलों के लिए विशेष सैल

4430 डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कर अपवचन को रोकने के लिये सुझाव देने हेतु एक विशेष सैल गठित करने का है,

(ख) यदि हा, तो प्रतिवर्ष औसतन कर अपवचन के कितने मामलो का पता चलता है और उसमें कितनी राशि का कर अन्तर्ग्रस्त होता है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा कर अपवंचन को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) जिन मामलो में आय के छिपाये जाने के कारण अर्थ-दण्ड लगाया गया है उनकी संख्या, वित्तीय वर्ष 1976-77 में इस प्रकार लगाए गए अर्थ-दण्डों की रकम के बारे में आंकडे नीचे दिए अनुसार है —

वित्तीय वर्ष	जिन मामलो में अर्थ-दण्ड लगाया गया उनकी सख्या	लगाए गए अर्थ-दण्ड की रकम
1976-77	6986	12 57 करोड़ रुपये
1977-78	8613	13.66 करोड़ रुपये